27 जनवरी : बोडो समझौते की छठी वर्षगांठ

शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की नई लहर

तकरीबन पांच साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने असम के प्रतिबंधित बोडो समूह के साथ समझौते की घोषणा की तो पूर्वोत्तर में इसे उज्ज्वल भविष्य की एक नई सुबह कहा गया। यही वह आधार भी था, जिस पर आगे बढ़कर दूसरे कई शांति समझौतों की नींव रखी गई। हिंसा का रास्ता छोड़ युवाओं ने देश के विकास में योगदान देने की शपथ ली तो समृद्धि और विकास की नई जमीन भी तैयार हुई। इसी नींव को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 दिसंबर को अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में लिया भाग...

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पूर्वोत्तर को प्रमुखता दी तो स्वाभाविक रूप से यह क्षेत्र पूरी केंद्र सरकार की प्राथमिकता बन गया। आज यह क्षेत्र अनेक विविधताओं के बावजूद निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 27 जनवरी 2020 को हुए बोडो शांति समझौते ने भी न केवल बोडोलैंड को दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौर से निजात दिलाई बल्कि इस क्षेत्र के लिए प्रगति का आधार स्तंभ भी बना।

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 72वीं पूर्ण बैठक में इसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार इस क्षेत्र को दुनिया के फोकस में लाकर खड़ा किया है, वह पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए युगांतकारी है। लंबे समय तक यह क्षेत्र दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहा था लेकिन पीएम मोदी ने अपने विजन और संवेदनशीलता से इस क्षेत्र को विकास के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 10 साल में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण जहां दिल्ली से पूर्वोत्तर की भौगोलिक दूरी कम हुई है, वहीं पीएम मोदी ने दिलों की दूरी को भी कम किया है। पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि अब तक 65 दौरे कर वह इस क्षेत्र में सबसे

पूर्वोत्तर में शांति और विकास के लिए हुए प्रमुख समझौते

29 नवंबर 2023
मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ भारत सरकार और मणिपुर सरकार का शांति समझौता।

27 जनवरी, 2020
भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के प्रतिनिधियों के बीच समझौता।

4 सितंबर 202
कार्बी-आंगलोंग समझौता, वर्षों पुराने असम के कार्वी क्षेत्र के विवाद को हल किया।

20 अप्रैल 2023
असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता।

29 दिसंबर, 2023
भारत सरकार, असम और उल्फा के बीच समझौता।

29 मार्च 2022
असम और मेघालय राज्य की सीमा के संदर्भ में समझौता।

27 अप्रैल, 2023
केंद्र सरकार, असम सरकार एवं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता।

10 अगस्त 2019
त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एनएलएफटी (एसडी) से समझौता।

16 जनवरी 2020
23 साल पुराने ब्रु-रिआंग शरणार्थी संकट समाधान के लिए केंद्र, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और ब्रु-रिआंग प्रतिनिधियों का समझौता।

> **"पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी दर्ज की गई है। 10,574 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है। कई शांति समझौतों के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने में भारत सरकार को सफलता मिली है।**
>
> – अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

हजारों नौजवानों ने हिंसा छोड़कर अपनाया विकास का रास्ता

पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर के हर राज्य में स्थाई शांति के लिए कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों से 10,574 हथियारबंद युवा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इससे पूर्वोत्तर में शांति आई है एवं विकास की नींव पड़ी है। एक अभूतपूर्व जनसमर्थन दिख रहा है। राज्यों के बीच जो सीमा विवाद थे, उनमें भी काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रगति हुई अनेक जिलों से अफ्स्पा को हटाया जा चुका है।

ज्यादा बार जाने वाले पीएम हैं तो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहां 700 दिनों से अधिक का रात्रि प्रवास किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चार दशकों तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की पुलिस का पूर्ण फोकस उग्रवाद के साथ लड़ने पर रहा है और अब जबकि उग्रवाद नहीं है, तब हमें नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार दे पाएंगे।

विशिष्ट रणनीति के साथ बढ़े आगे

सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया है और हर राज्य के लिए एक विशिष्ट रणनीति बनाकर पिछले 10 साल में आगे बढ़ा है। इस रणनीति का ही परिणाम है कि पुलिस, सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने मिलकर पूर्वोत्तर में एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित करने में सफलता पाई है। पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी हुई है। ●